GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-795
ANSWERED ON-MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944 (SAKA)

Gold Smuggling

795. PROF. SOUGATA RAY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

a) whether the reporting of gold smuggling cases has increased sharply in the country;

b) if so, the details of such cases reported during each of the last three years, State-wise;

c) the steps taken by the Government to curb gold smuggling into the country;

d) whether the Government suspects the role of gangs, who finance the anti-national elements; and

e) if so, the details thereof and the reaction of the Government thereto?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) & (b) Details enclosed as per Annexure-A.

(c) The Government makes policy interventions and takes operational measures to check smuggling.

To deter smuggling of gold, Customs field formations and Directorate of Revenue Intelligence (DRI) keep constant vigil and take operational measures such as passenger profiling, risk based interdiction and targeting of cargo consignments, non-intrusive inspection, rummaging of aircrafts and coordination with other agencies. Modus Operandi Circulars related to new modus/ method used by the gold smugglers are issued from time to time.

(d) & (e) In last three years, National Investigation Agency (NIA) has conducted investigations and filed charge sheets in three cases of gold smuggling.

******

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.795

जिसका उत्तर सोमवार, सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/ 21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

सोने की तस्करी

795. प्रो. सौगत रे:

क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोने की तस्करी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

ग) देश में सोने की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

घ) क्या सरकार को ऐसे गिरोहों की भूमिका पर संदेह है, जो राष्ट्र-विरोधी तत्वों को वित्तपोषित करते हैं; और

ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) & (ख): विवरण अनुलग्नक-**क** के अनुसार संलग्न है।

(ग): सरकार तस्करी की रोक के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और संचालनात्मक उपाय करती है।

सोने की तस्करी रोकने के लिए, सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाएं और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) निरंतर निगरानी रखते हैं तथा यात्री प्रोफाइलिंग, जोखिम आधारित प्रतिबंध व कार्गो खेपों को लक्षित करने, घुसपैठ निरोधी निरीक्षण, वायुयानों की तलाशी और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय जैसे संचालनात्मकउपाय करती हैं। सोने के तस्करों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नई कार्यप्रणाली/पद्धति से संबंधित कार्यप्रणाली परिपत्र समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

(घ) & (ङ): पिछले तीन वर्षों में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने सोने की तस्करी के तीन मामलों में जांच की और चार्जशीट दायर की है ।

******

अनुलग्नक-क

12.12.2022 के लिए लो.स. अतारांकित प्रश्न सं. 795

राज्यवार आंकड़े

राज्य/ कें.शा.प्र.	कैलेंडर वर्ष	सोने की जब्ती के मामलों की सं.	जब्त सोने की मात्रा (कि.ग्रा. में)
पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा)*	2019	50	166.849
	2020	49	242.845
	2021	54	296.580
	2022 (नवम्बर तक)	60	191.062
बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड*	2019	91	79.591
	2020	61	86.293
	2021	93	138.476
	2022 (नवम्बर तक)	89	130.380
गोवा	2019	11	5.496
	2020	7	7.735
	2021	13	12.215
	2022 (नवम्बर तक)	14	8.635
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव*	2019	137	93.155
	2020	114	50.760
	2021	73	36.610
	2022 (नवम्बर तक)	141	116.355
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, लेह एवं लद्दाख*	2019	502	567.421
	2020	309	404.124
	2021	359	379.125
	2022 (नवम्बर तक)	528	431.611
कर्नाटक	2019	207	89.000
	2020	103	52.260
	2021	173	91.755
	2022 (नवम्बर तक)	130	90.224
केरल	2019	1073	725.251
	2020	672	406.390
	2021	738	586.952
	2022 (नवम्बर तक)	948	690.134
महाराष्ट्र	2019	812	674.841
	2020	389	191.429
	2021	210	119.223
	2022 (नवम्बर तक)	484	473.909
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़*	2019	2	13.073
	2020	5	10.606
	2021	7	47.015
	2022 (नवम्बर तक)	6	16.354
ओड़िशा	2019	11	17.850
	2020	2	0.820
	2021	0	0.000
	2022 (नवम्बर तक)	3	2.214
तमिलनाडु	2019	1186	652.542
	2020	676	375.007
	2021	521	322.114
	2022 (नवम्बर तक)	809	439.787
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश*	2019	117	177.790
	2020	94	104.330
	2021	95	98.130
	2022 (नवम्बर तक)	162	124.334
पश्चिम बंगाल	2019	205	410.184
	2020	86	221.982
	2021	109	255.186
	2022 (नवम्बर तक)	214	368.619
कुल	**2019**	**4404**	**3673.04336**
	2020	**2567**	**2154.5812**
	2021	**2445**	**2383.38128**
	2022 (नवम्बर तक)	**3588**	**3083.61802**

* पृथक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण राज्यों/ कें.शा.प्र. को समूहीकृत किया गया था।